जवाहर लाल नेहरू
राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन

शहर विकास योजना सूत्र

जेएनएनयूआरएम

विषय सूची

टूल किट

I शहर विकास योजना (सीडीपी)

II. शहर विकास योजना तैयार करना

III. शहर निर्धारण:–मौजूदा अवस्था का विश्लेषण

IV. शहर के लिए विजन तैयार करना

V. नीतियों पर कार्य

VI. शहरी निवेश योजना (सीआईपी) और वित्तीय जुटाव नीति

VII. सारांश

परिशिष्ट

टूल किट

यह टूल किट शहर शासकों तथा दूसरी प्रतिभागी संगठनों को जैसे की राज्य स्तरीय तथा शहर स्तरीय जल आपूर्ति तथा सीवेज बोर्डों और शहर विकास योजनाओं (सीडीपी) का सूत्रण करने वाले विकास प्राधिकरणों को सहायता प्रदान करने के लिए तैयार की गई है। यह टूल किट शहर विकास योजनाओं (सीडीपी) के कार्य क्षेत्र को निरुपित करती है क्योंकि यह योजना जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन से प्रकट हुई है। यह डेटा की जरूरतों को सूचित करती है और विश्लेषण के लिए पद्धति के लिए पद्धति इजाद करती है जो दिक्कतों और संसाधनों की वाजिब पहुंच तक उनके इस्तेमाल के लिए एक उपाय है और उन शहरों के लिए तुलनात्मक लाभ है और उनके भावी विकास के लिए एक मध्यम से दूरगामी सोच का निर्धारण करती है। इस टूल किट में उन मुख्य-मुख्य मुद्दों को पहचान करने की तरकीब दी गई हैं जिनका कि पता लगाने की जरूरत है और शहर अब किस स्थिति में है और वे किस जगह ले जाना चाहते हैं इस के बीच की दूरी को पाटने के लिए शहर के पास जो विकल्प हैं, उनका पता लगाने के लिए तैयार की गयी है।

I शहर विकास योजना

शहर विकास योजना (सी.डी.पी.) किसी शहर के भावी विकास के लिए एक परिदृश्य तथा एक विजन दोनों ही हैं। ये शहर के विकास की मौजूदा अवस्था को, अर्थात अभी हम कहां पर हैं? को प्रस्तुत करती है। ये परिवर्तनों के निर्देशों अर्थात हम शहर को कहां ले जाना चाहते हैं, को निर्धारित करता है। यह उन प्रणोदी की पहचान करता है कि हमारी वे कौन सी जरूरतें हैं जिनका पता हमें प्राथमिकता के आधार पर लगाना है? ये हमें वैकल्पिक रास्ते नीतियों उन दखल अन्दाजियों को भी सुझाता है जिनसे कि परिवर्तन लाया जा सकता है कि इस विजन को प्राप्त करने के लिए हमें कौनसी दखल अंदाजी करनी है? जिसके भीतर रह कर हम पहचान की जाने वाली जरूरतों तथा उनके कार्यान्वयन को प्रोजेक्ट करते हैं। ये हमें निवेश निर्णयों का मूल्यांकन करने के लिए एवं तार्किक तथा सुसंगत फ्रेमवर्क संस्थापित करती है।

ये शहर विकास योजना आर्थिक रूप से उत्पादक, कुशल, उचित तथा अनुकूल शहरों के सृजन हेतु जवाहर लाल नेहरू शहरी नवीकरण मिशन (जनरम) के लक्ष्यों पर आश्रित हैं। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए एक उपाय के रूप में ये सीडीपी आर्थिक तथा सामाजिक अवसंरचनाओं के विकास तथा उन नीतियों पर प्रकाश डालती है जो खासतौर से शहरी गरीबों को प्रभावित करने वाले मुद्दों से संबंधित हैं, नगर निगम सरकारों को मजबूत करते हैं, और उनके वित्तीय लेखाकरण तथा बजटीय सिस्टमों व प्रक्रियाओं को बल देते हैं और जवाब देही तथा पारदर्शिता बरतने के लिए नियमों के सृजन करते हैं तथा कानूनी व दूसरी उन अड़चनों के विलापन जो भूमि तथा आवासीय बाजारों का दमन करते हैं। यह उन शहरी क्षेत्र के सुधारों को अपनाने के लिए जो कि सीधे ही शहर आधारित अवसंरचनाओं में निवेश करने में मदद करते हैं, शहरों को एक आधार प्रदान करती है।

किसी भी शहर के लिए यह अनिवार्य है कि वह उसके भावी विकास के लिए सिलसिलेवार सोचे और यह निर्धारित करे कि उसका भावी स्वरूप कैसा होना चाहिए।

II शहर विकास योजना तैयार करना

शहर विकास योजना तैयार करना एक बहुस्तरीय प्रक्रिया है जिसमें निम्न स्तर शामिल हैं।

I मौजूदा अवस्था का गहन विश्लेषण करना, जिसमें जनसांख्यिकी, आर्थिक, वित्तीय, अवसंरचनात्मक, भौतिक, पर्यावरणीय और संस्थागत पहलुओं को समाहित हो:– इस चरण का उद्देश्य शहर के विकास की स्थिति सिस्टम तथा प्रक्रियाओं व इसी प्रकार से इसके संस्थागत व वित्तीय परिप्रेक्ष्य में समान रूप से शहर की मौजूदा अवस्था का पुनर्वलोकन तथा विश्लेषण करना है। यह चरण शहर के विकास में उसकी सामर्थ्यों तथा कमजोरियों की पहचान करने और यह समझ प्रदान करने कि मौजूदा सैट-अप में सेवाएं मुहैया करायी जाने में कौन सी बाधाएं है तथा मौजूदा सेट-अप के भीतर प्रबंधन और अच्छी बेहतर सेवाओं के प्रावधान के लिए तथा क्या योगदान हो सकता है, के लिए बना है। ये चरण इस बात का अवसर प्रदान करता है कि किसी शहर के अद्वितीय लक्षणों, जिनका की दूसरे शहरों से तुलना करके पता लगाया जा सकता है, को उजागर करें।

I परिदृश्य का विकास एवं शहर का विजन:– मुख्य स्टेक होल्डर्स तथा सिविल सोसाइटी के परामर्शों को मिलाकर पहले चरण के विश्लेषण के परिणामों का उपयोग करते हुए यह चरण भावी विकास के लिए एक विजन का विकास करने के लिए बना है-इसमें इस शेयर परिदृश्य का विकास किया जाता है कि मध्यम अवधि में शहर का स्वरूप क्या हो। यह आशाओं तथा सभी के लिए जल जैसे के अभिव्यक्त अर्थों में भावी निर्देश का सामूहिक विजन है।

I शहर किस अवस्था में है और उसे किस स्तर पर ले जाना चाहते हैं इसके बीच की दूरी को पाटने के लिए नीति का निरुपण करना:– इसमें इस चरण में विजन प्राप्त करने हेतु नीतियां तथा हस्तक्षेपों की पहचान की जाती है और भावी विकास का परिदृश्य तैयार किया जाता है। इस चरण का इस्तेमाल सर्वप्रथम विकल्पों तथा नीतियों की पहचान करने के लिए किया जाता है फिर इसका इस्तेमाल जनरम ''के'' लक्ष्य एवं उद्देश्यों के लिए उनके योगदान के संदर्भ से मूल्यांकन तथा नीतियां तय करने के लिए किया जाता है। चुनी गई कार्य नीतियों को कार्यक्रम में उतारा जाता है और फिर उसे इस चरण में प्रोजेक्ट करते हैं। ये एक ऐसा चरण है जहां पर कि किसी शहर को इस बात का निर्णय करने की जरूरत होती है कि कौन कौन से कार्यक्रम विजन तथा मध्य अवधि परिदृश्यों में अपना अधिकाधिक योगदान करेंगे। यह एक ऐसा चरण है जहां पर कि नीतियों की प्राथमिकतांए, कार्यक्रम तथा प्रोजेक्ट्स की वरीयताएं सुनिश्चित करने के लिए समुचित सलाहत्मक प्रक्रियाओं सहित मानदण्ड चुने जाते हैं।

IV. शहर निवेश योजना (सीआईपी)तैयार करना तथा वित्तीय नीति:– निवेश योजना तथा वित्तीय नीति तैयार करना सीडीपी के अभिन्न अंग है। उदाहरण के लिए यह एक औसतन निवेश योजना है जो सूचित करता है कि 10/7 के मौजूदा स्तर से 24/7 जलापूर्ति मुहैया कराने में आने वाली लागत क्या होगी। ये 1,00,000 एमएलडी से 1,50,000 एमएलडी की क्षमता वाले जल संयंत्र की धारित क्षमता को बढ़ाने के लिए किसी प्रोजेक्ट की अनुमानित वित्तीय लागत नहीं है। इस चरण में निर्णय कराना ही योजना है कि जो विजन के लिए वित्त जुटाने के वैकल्पिक स्रोतों का विचार करती है और नीति तथा कार्याक्रमों के लिए सहयोग करती है।

सीडीपी को निरुपित करने की प्रक्रिया इस चार्ट में चित्रित की गयी है (चित्र देखें)

बहुस्तरीय कार्य

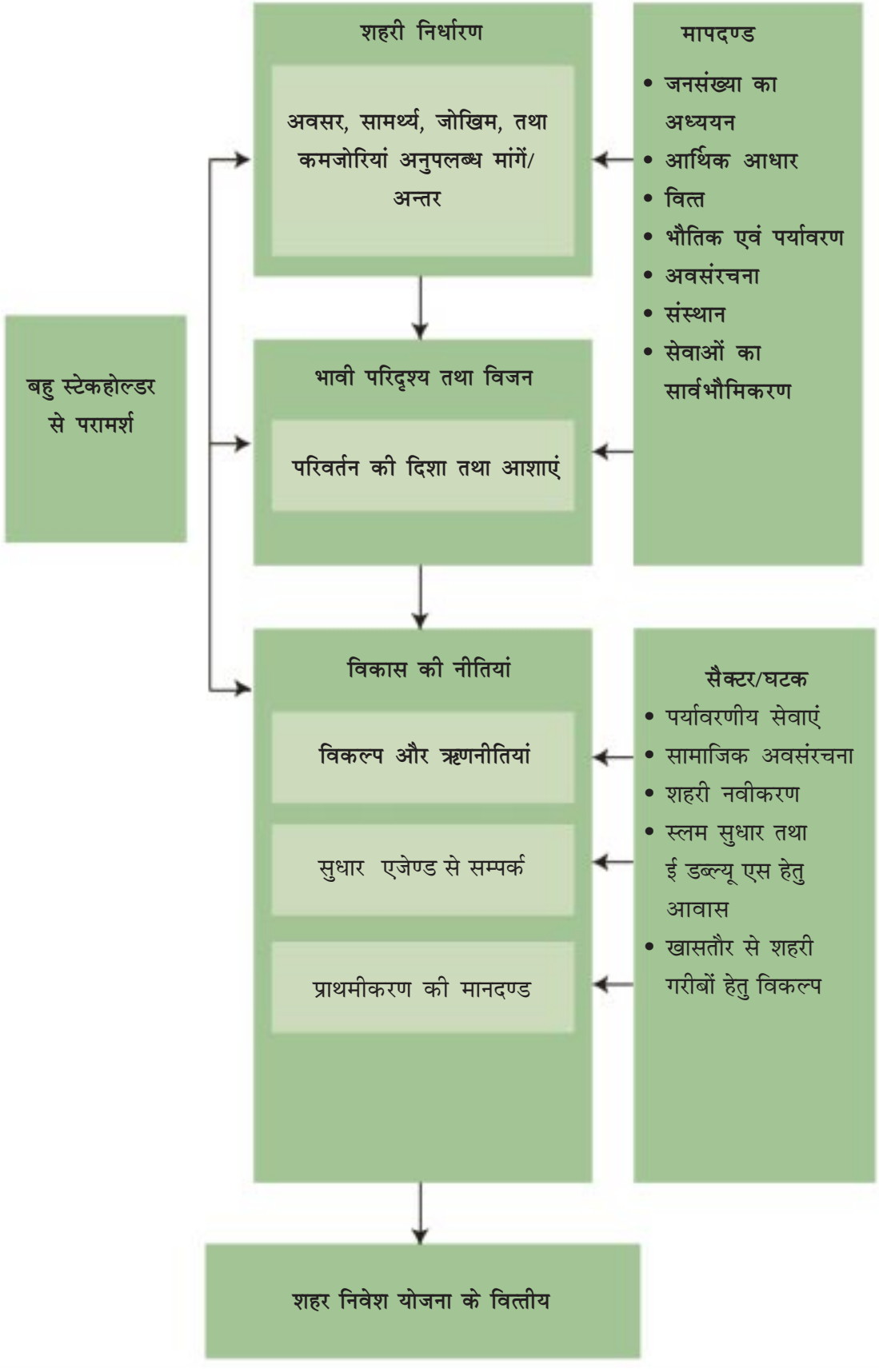
शहरी निर्धारण
अवसर, सामर्थ्य, जोखिम, तथा कमजोरियां अनुपलब्ध मांगें/ अन्तर
मापदण्ड
• जनसंख्या का अध्ययन
• आर्थिक आधार
• वित्त
• भौतिक एवं पर्यावरण
• अवसंरचना
• संस्थान
• सेवाओं का सार्वभौमिकरण
बहु स्टेकहोल्डर से परामर्श
भावी परिदृश्य तथा विजन
परिवर्तन की दिशा तथा आशाएं
विकास की नीतियां
विकल्प और ऋणनीतियां
सुधार एजेण्ड से सम्पर्क
प्राथमीकरण की मानदण्ड
सैक्टर/घटक
• पर्यावरणीय सेवाएं
• सामाजिक अवसंरचना
• शहरी नवीकरण
• स्लम सुधार तथा ई डब्ल्यू एस हेतु आवास
• खासतौर से शहरी गरीबों हेतु विकल्प
शहर निवेश योजना के वित्तीय

III. शहर निर्धारण: मौजूदा अवस्था का विश्लेषण

मौजूदा अवस्था का विश्लेषण किसी भी सी डी पी के सूत्रण का पहला चरण है। इस विश्लेषण का प्रयोजन वास्तविक निर्धारण करना है कि शहर कहां पर और शहर को किस दिशा में ले जाना है और उसकी सामर्थ्य तथा कमियां कौन-कौन सी हैं। यह चरण उस की जन सांख्यिकी, आर्थिकी, वित्तीय, अवसंरचनात्मक, भौतिक तथा पर्यावरणीय और शहर के संस्थागत पहलुओं के गहन विश्लेषण के लिए बना है। इसमें सेवाएं प्रदान करने, प्रबंधन तथा उसके अभिशासन की पेचीदगियों की जांच करनी चाहिए।

जन सांख्यिकी

किसी भी सीडीपी के सूत्रण में एक शहर की जन सांख्यिकी विशेषताएं एक मुख्य घटक होती हैं और इनके विश्लेषण जनसंख्या वृद्धि के पैटर्न के अर्थों में तथा शहर में फैले इसके स्थानिक के आधार पर किए जाते हैं। ये विश्लेषण निम्नलिखित प्रश्नों पर परिलक्षित होना चाहिए जैसे कि क्या जनसंख्या वृद्धि (किस पैमाने पर) अत्यधिक है, औसत अथवा औसत से नीचे है? वे कौन से कारक है जो वृद्धि के मूल में है–प्राकृतिक वृद्धि, प्रव्रजन, कार्यधिकार क्षेत्र में परिवर्तन? व्यापक अर्थों में प्रव्रजन की विशेषताएं क्या हैं? आश्रय, सेवाओं तथा अवसंरचना के लिए जनसंख्या वृद्धि की क्या पेचीदगियां होती हैं? आय के अर्थों में शहर की जनसंख्या के सामाजिक संयोजन क्या है और आश्रय व सेवाओं की पहुंच कैसी है? शहर के भीतर गरीबी का स्तर क्या है? क्या शहर में गरीबी का स्तर बढ़ अथवा घट रहा है? क्या झुग्गी झोपड़ी का मामला शहर की प्रमुख समस्या है? क्या यह बढ़ती हुई समस्या है या ऐसी कोई बात है जो स्थिरीकरण के लक्षण प्रकट करती है?

मूल्यांकन में जनसंख्या की आयु तथा लिंग संयोजन की जांच करने के लिए इस विश्लेषण को आगे बढ़ाया जा सकता है ताकि स्कूल जाने वाले बालकों तथा श्रम बल के आकार (व्यक्ति) को सभी प्रकार से जांचा जा सके।

सारणी 1: जनसंख्या वृद्धि

वर्ष	जन समुदाय (लाख में)	औसत वार्षिक दृष्टि दर %
1981		
1991		
2001		
2005 (अनुमानित)		
2011 (प्रोजेक्ट की गयी)		
सरल रेखा पद्धती से प्रोजैक्ट करें		

सारणी 2: वृद्धि का संयोजन

संघटन	वर्षों के दौरान जनसंख्या वृद्धि %			
वर्ष	1981-91	कुल का %	1991-2001	कुल का %
प्राकृतिक वृद्धि				
प्रव्रजन से				
कार्य अधिकार क्षेत्र परिवर्तन				
कुल वृद्धि				

जेएनएनयूआरएम

सारणी 3: जनसंख्या के सामाजिक संयोजन	
वर्ष	गरीबों की संख्या
1993/94	
1999/00	
2004/05 (अनुमानित	
गरीबी रेखा से नीचे)	

सारणी 4: झुग्गी झोपड़ी वालों की मूल सेवाओं तक पहुंच				
वर्ष	झुग्गी झोपड़ी वालों की संख्या	इन सुविधाओं को पाने वाले झुग्गी झोपड़ी वालों का प्रतिशत		
		जल आपूर्ति	निकासी सिस्टम	ठोस सेवा संग्रहण
1991				
2001				
2005 (अनुमानित)				

आर्थिक आधार

इसमें आर्थिक आधार उन प्रमुख क्षेत्रों को परिलक्षित करता है जो शहर की आर्थिक स्थिति को बताता है। ये क्षेत्र उत्खनन तथा विनिर्माण, अवसरंचना जैसे कि ऊर्जा तथा जनोपयोगी सुविधाओं, वित्तीय तथा बैंकिंग सेवाओं, सार्वजनिक सुविधाओं, पर्यटन या धार्मिक से जुड़े हो सकते हैं। इस विश्लेषण का मूलमंत्र शहर की आर्थिकी के प्रमुख क्षेत्रों की पहचान करने तथा उनका परीक्षण करने में निहित है यदि वह प्रमुख क्षेत्रों के भीतर वृद्धि मध्यम अवधि फ्रेमवर्क में बनी रहने की संभावनाएं बताती हैं? यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि आर्थिक आधार में हाल ही में स्थानान्तरण हुए हैं और कारक जो स्थानांतरण जैसे व्यक्त किए गए हैं और उनका शहर की आर्थिकी पर दीर्घावधि प्रभाव क्या होगा। वह बहुत जरूरी है कि शहर की आर्थिकी में अनौपचारिक क्षेत्र की भूमिका व योगदान को भी ध्यान में रखा जाए।

सारणी 5: आर्थिक आधार, पंजीकृत विनिर्माण और सेवाएं		
	वर्ष	
	2001	2005 (अनुमानित)
विनिर्माण		
रोजगार		
उत्पादन (करोड़ रुपये में)		
मूल्य वृद्धि (करोड़ रुपये में)		
सेवाएं (आयकर आदि)		
रोजगार		
उत्पादन और कारोबार की मात्रा (करोड़ रुपये)		
मूल्य जमा (करोड़ रुपये)		

सारणी 6: आर्थिक आधार, व्यवस्था वितरण, 2001		
व्यवसाय श्रेणी	वर्करों की संख्या	कुल का प्रतिशत
प्राथमिक क्षेत्र		
घरेलू उद्योग		
विनिर्माण		
विद्युत, गैस तथा जलापूर्ति		
निर्माण		
परिवाहन, भण्डार तथा संचार		
बैंकिंग तथा बीमा		
व्यापार तथा कारोबार		
सेवाएं		
कुल		

वित्तीय रूपरेखा

शहर का वित्तीय प्रोफाइल शहर की वित्तीय हालत और शहर की क्षमता को सूचित करता है ताकि वह इसके वित्तीय साधनो का प्रबंध करने में समर्थ हो जाए और निर्धारित मानकों और स्टैण्डर्ड पर अवसंरचनात्मक सेवाओं को बनाए रखने के लिए अपने संसाधनों का जुटाव कर सकें। इस विश्लेषण में निम्न के निर्धारण पर ध्यान केन्द्रित करना चाहिए: (I) शहर की सरकार की वित्तीय स्थिति (सेवा संबंधों के लिए उत्तरदायी दूसरे पैरास्टेटल संगठनों को भी रखें) (II) बकाया ऋणों सहित मौजूदा परिसंपत्तियों तथा देयताओं की स्थिति (III) नगर निगम सरकारों के वित्तीय साधनों में अन्तर-सरकारी अन्तरणों की भूमिका का विश्लेषण करने। इसमें खासतौर से ऐसे प्रश्नों को अवश्य शामिल किया जाना चाहिए: नगर निगम सरकारों के पास राजस्व के स्रोत क्या हैं? क्या नगर नियम सरकारें अपने खुद के संसाधनों से आवर्ती खर्चों के इसके वर्तमान स्तर को पूरा करने में सक्षम है? क्या यह इसके ''खुद के संसाधनों'' को अनुकूलतम इस्तेमाल में सक्षम हैं? स्थानीय कर निर्धारण तथा संकलन प्रक्रियाओं की कसौटी कितनी प्रभावी है? अपने आवर्ती खर्चों को पूरा करने के लिए राज्य सरकारों के अन्तरण पर शहर सरकारें किस सीमा तक आश्रित हैं? शहर सरकारों को क्या चाहिए और राजस्व बढाने की शक्तियों व अन्तर सरकारी कार्यों के कारण राजस्व बढाने में क्या वे समर्थ है, या वे उनका अकुशलता से उपयोग करते हैं और शहर सरकारों द्वारा आवेदन? यदि नगर निगम सेवाओं पर व्यय के स्तर दूसरी बातों अर्थात् गरीब क्षेत्रों की तुलना में कुछेक क्षेत्रों के पक्ष में विषम है तो इसकी जांच करना उपयोगी होगा। कौन-सी बजटीय तथा लेखाकरण पद्धतियां प्रयोग में लाई गई है? क्या शहर सरकारों की वित्तीय लेखाएं ''प्राप्य'' तथा ''देयों'' को प्रतिबिम्बित करती हैं?

अनेक नगर निगमों में स्थानीय सरकारों के लिए राजस्व का प्राथमिक स्रोत सम्पति कर ही होता है। सम्पति कर के सिस्टम के विश्लेषण में कर निर्धारण तथा वसूली के तरीकों, राजस्व की लागत को वसूलने के अनुपात, और अपवादों के कारण लीकेज, घाटों के प्राकलन आदि पर ध्यान देना चाहिए। सामान्यत: उपयोगकर्ता प्रभारों को नियत करने में क्या मानदण्ड अपनाया गया है? कुशलता का स्तर क्या है और स्थानीय कराधार, व्यय की कुशलता तथा साम्यता का स्तर क्या है और उपयोगकर्ता की निशुल्क नीतियां क्या हैं? स्थानीय राजस्व के लिए शहरी गरीब कितने राजस्व का योगदान करते हैं? स्थानीय व्ययों से वे कितना लाभ प्राप्त करेंगे?

सारणी 7: नगर निगम राजस्व आय				
वर्ष	राजस्व लेखा में प्राप्ति (रुपये लाख में)			
	कर	बिना कर	अनुदानों सहित अंतरण	योग
2001/02				
2002/03				
2003/04				
2004/05				

सारणी 8: नगर निगम राजस्व व्यय					
वर्ष	राजस्व लेखा में व्यय (रुपये लाख में)				
	संस्थापन (मजदूरी और वेतन)	कार्यालय तथा अनुरक्षण	ब्याज भुगतान	अन्य	योग
2001/02					
2002/03					
2003/04					
2004/05					

सारणी 9: नगर निगम पूंजी प्राप्तियां					
वर्ष	पूंजी प्राप्तियां (रुपये लाख में)				
	राज्य सरकार (रुपये लाख में)		वित्तीय संस्थाओं से	बाजार से	योग
	ऋण	अनुदान			
2001/02					
2002/03					
2003/04					
2004/05					

सारणी 10 : शहर स्तरीय जलापूर्ति तथा सीवेज बोर्डों को वित्तीय सहायता		
वर्ष	खर्चे (लाख रुपये)	आय (लाख रुपये)
2001/02		
2002/03		
2003/04		
2004/05		

अवसंरचना

अवसंरचना रूपरेखा किसी शहर के अवसंरचना की मौजूदा अवस्था तथा शहर के उपयोगिता सिस्टमों का उल्लेख करती है। ये कवरेज, प्रमात्र व गुणवत्ता के अर्थों में अवसंरचनात्मक सेवाओं की पर्याप्तता अथवा अपर्याप्तता को सूचित करती है और अवसंरचना सेवाओं की पर्याप्तता अथवा अपर्याप्तता को सूचित करती है और अवसंरचना सेवाओं के अपर्याप्त विकास के लिए उत्तरदायी कारकों की पहचान करने का प्रयास करती है। ये विभिन्न अवसंरचनात्मक सेवाओं की मांग व पूर्ति के बीच के अन्तर को मापता है और उन कारकों की जांच करता है जो अन्तरों को व्यक्त करते हैं। उदाहरण के लिए क्या (I) निवेश की कमी, जल तथा ऊर्जा के क्षेत्र में आमतौर से लीकेज तथा चोरियों के कारण; (II) उन नीची दरों जो निवेश को एक गैर-प्रोत्साहन के रूप में पूरा करती है; (III) या फिर संस्थागत अपखण्डन के कारण से जल अथवा ऊर्जा की उपलब्धता में अपर्याप्तता बनी है। ये दी जाने वाली सेवाओं की लागत की समीक्षा करती हैं और उनसे उत्पन्न वसूलियों से उनकी तुलना करती हैं। शहर के भीतर सेवा मुहैया कराने की संवितरणीय विशेषताएं क्या हैं? विभिन्न सामाजिक-आर्थिक समूहों से प्राप्त हुई सेवाओं के स्तर में क्या कोई अंतर है?

इस विश्लेषण के सबसे महत्वपूर्ण पहलू इस तथ्य की पहचान करने में छिपा है कि अवसंरचना तक अपर्याप्त पहुंच ही विकास की एक सबसे अहम कठिनाई है। सार्वजनिक सेवाओं को मुहैया कराने की विशेषताओं और गुणवत्ता का निर्धारण करने से भिन्न यह बात अधिक महत्वपूर्ण है कि उन कारकों को सुनिश्चित किया जाए जो कि अवसंरचना विकास को बाधित कर रहे हैं। क्या ये कारक वित्तीय संस्थागत या फिर दूसरे हैं?

सारणी 11 : अवसंरचना स्थिति

जल उपलब्धता	स्थापित क्षमता (एमजीडी) जारी/
	प्रतिदिन (एम जी डी)
जल आपूर्ति का स्रोत	शहर सीमा के भीतर
	10-15 वर्ग. कि.मी.
	50-100 वर्ग कि. मी.
जल प्रदान किया	सार्वजनिक जल आपूर्ति द्वारा पूरित संख्या का प्रतिशत
	प्रतिव्यक्ति आपूर्ति (एलपीसीडी)
	आपूर्ति की अवधि (प्रति घंटा)
गंदे जल का निपटाना	प्रतिदिन सृजित गंदा जल (एमएलडी)
	निपटाना (भूमिगत सीवरों) की क्षमता (एमएलडी)
	वर्तमान में कार्य क्षमता (एमएलडी)
	भूमिगत सीवरों से जुडे घरों का प्रतिशत
ठोस कचरा	प्रतिदिन इकट्ठा हुआ कचरा (टन/दिन)
	प्रतिदिन एकत्रित (टन/दिन)
बरसाती जल की निकासी	वार्षिक वर्षा (सेंटीमीटर)
	बरसाती जल निकासी की लंबाई (किलोमीटर)
सड़क और सड़क परिवहन	नगर निगम सड़क (किलोमीटर)
	राजकीय सड़क (किलोमीटर)
	जन परिवहन
	बसें (संख्या)
	बस क्षमता/सवारियां
	निजी पंजीकृत वाहन
सड़कों पर रोशनी	संख्या
	घेरा हुआ क्षेत्रफल प्रतिशत

सारणी 12 : शहर अवसंरचना में लागत की वसूली						
अवसंरचना	सेवा प्रावधान पर उपगत लागत (रुपये लाख में)			सीधी प्राप्तियां (रुपये लाख में)		
	2002/03	2003/04	2004/05	2002/03	2003/04	2004/05
जल आपूर्ति						
सीवर तथा सफाई						
कचरा एकत्रण						
सार्वजनिक बस सेवा						

सारणी 13 : शहर अवसंरचना में औसत निवेश स्तर		
अवसंरचना	सार्वजनिक निवेश (करोड़ रुपये में)	निजी निवेश (करोड़ रुपये में)
जल आपूर्ति		
सीवर तथा निकासी		
ठोस कचरा		
सड़कें (नगर निगम)		
स्ट्रीट लाइटें		
बरसाती जल निकासी		
योग		

भौतिक व पर्यावरण पहलू

किसी शहर का भौतिक पहलू उसके स्थलाकृति विज्ञान (उस सीमा तक जहां तक वह विकास पर एक नियंत्रण के रूप में कार्य करता है) प्राकृतिक निकासी सिस्टम और भूमि की उपलब्धता से जुड़ा है। यहां बताए गए इन सेवा मसलों में निर्धारण का यह तत्व विशेष रूप से भूमि की उपलब्धता तथा भूमि के उपयोग संगठन से जुड़ा होना चाहिए। इसमें उपलब्ध कुल भूमि, विभिन्न प्रयोगों तथा उद्देश्यों के लिए आवंटन को सूचित करना चाहिए। भले ही ये कुछ सुनिश्चित सिद्धान्तों के आधार पर किए गए हों और इनकी सुसंगतता शहर की व्यापक आर्थिकी तथा शहर के अवसंरचनात्मक आधार से होनी चाहिए। इस विश्लेषण में भूमि की उपलब्धता की पर्याप्तता का निर्धारण अन्तर्विष्ट होता है और ये विधिक तथा सांविधिक उपबन्धों जैसे कि बाजार के लिए भूमि उपलब्ध कराने में शहरी भूमि (सीमा तथा नियामक) अधिनियम, 1976 की भूमिका को फोकस करता है। इसमें सर्वेक्षण दिया होता है और इसमें नवीकरण क्षेत्रों की पहचान करने के लिए मानकदण्ड स्थापित करके उस क्षेत्र का रेखाचित्र तथा वह अवसंरचना दी जाती है जिसका कि नवीकरण करना जरूरी होता है।

कहा गया है कि शहरी नियोजन विकास का एक महत्वपूर्ण कारक है अत: यह अनिवार्य है कि निम्न प्रश्नों पर प्रकाश डाला जाए जैसे कि विभिन्न प्रयोगों द्वारा शहरी भूमि का कितना प्रतिशत भाग कब्जाया हुआ है? हाल ही के वर्षों में भूमि के उपयोग में क्या परिवर्तन हुए है? शहरी भूमि बाजार की विशिष्टताएं क्या हैं? भूमि के उपयोग के नियंत्रण हेतु क्या पद्धति अपनायी गयी हैं?

पर्यावरण का विश्लेषण प्राथमिक रूप में जनसंख्या वृद्धि के प्रभाव, आय में परिवर्तनों, आर्थिक गतिविधियों के फैलाव, मोटरीकरण से सीधे-सीधे जुड़ा है और इसी प्रकार से पर्यावरण तथा पर्यावरण से जुडी सेवाएं जैसे कि

वायु और जल की गुणवत्ता, गन्दा जल और विषैले तथा खतरनाक कचरे सहित ठोस कचरों के सम्मिश्रण से भी संबंधित है। ये शहर के भीतर की पर्यावरणीय अवस्थाओं के स्वास्थ्य प्रभावों को निर्धारित करने का एक मूलमंत्र है। विश्लेषण में शहर के अंदर संभावित बाढ़, भूकम्प या दूसरी राष्ट्रीय महाविपदाओं जैसी आपदाओं का शामिल करना भी उतना ही जरूरी है।

सारणी 14: पर्यावरण सेवाएं

पर्यावरण सेवाएं	गुणवत्ता
वायु	
जल	
गंदा जल	
ठोस जल	

सारणी 15: भूमि आपूर्ति (हैक्टेयर)

वर्ष	विकसित भूमि (हैक्टेयर)	प्रयोग में आ रही अविकसित और विकासाधीन भूमि (हैक्टेयर)
2001/02		
2002/03		
2003/04		
2004/05		

सारणी 16: भूमि उपयोग की विवेचना (ब्रेक अप)

श्रेणी	प्रतिशत क्षेत्र (वर्ष का उल्लेख करें)
आवासीय	
वाणिज्य सम्बन्धी	
औद्योगिक	
सार्वजनिक अर्द्धसार्वजनिक	
मनोरंजन	
परिवहन	
कृषि योग्य और जल निकाय	
विशेष क्षेत्रफल*	
कुल क्षेत्रफल	

**उन क्षेत्रों के ब्यौरे दें जिनके कि विशेष क्षेत्रों अर्थात् शहरी, ग्रामीण, स्लम इत्यादि के रूप में परिभाषित किया गया है।*

सारणी 17: आवासीय तथा अवसंरचना स्टाकों के नवीकरण का लागत अनुमान–2005	
शहर स्टॉक	**प्रतिशत क्षेत्रफल (हैक्टेयर)**
आवासीय	
अवसंरचना	
Ø सड़कें और गलियां	
Ø जल वितरण नेटवर्क*	
Ø सीवर तथा नालियां*	
औद्योगिक	
Ø हटा दी गई, प्रौद्योगिकी और भौतिक	
Ø दूसरे उपयोग कर्ताओं से असंगतता	
व्यापारिक जिले	
Ø हटा दिए गए	
Ø दूसरे उपयोग कर्ताओं से असंगतता	
Ø मापन की समूचित इकाई का उपयोग करें जैसे कि वितरण नेटवर्क के लिए किलोमीटर का	

संस्थाएं

शहर का प्रबंध तथा अभिशासन अनेक संस्थाओं तथा संगठनों द्वारा किया जाता है। इस संबंध में, शहर एक मिश्रित अस्तित्व है। इस विश्लेषण का उद्देश्य संगठनात्मक ढांचे को प्रस्तुत करना है क्योंकि ये अवसंरचनात्मक सेवाओं को मुहैया कराने तथा उनके प्रबंधन से जुड़ा है। जैसे कि कौन क्या करता है, और मौजूदा संस्थागत अवसंरचनाओं के कार्य की क्षमता तथा कुशलता का मूल्यांकन करना। प्राय: जिम्मेदारियां एक दूसरे पर डाल दी जाती हैं और प्राय: ऐसा भी होता है कि समन्वय के लिए बिना किसी मंच के जिम्मेदारियों का संविभाजन भी हो सकता है। अत: इस विश्लेषण को इस प्रकार आयोजित किए जाने की जरूरत है कि कार्य के मौजूद आवंटन पर और इसकी वित्तीय जिम्मेदारियों की मुख्य समस्याओं पर छायांकित प्रकाश पड़े और उस सीमा तक इन्हें उजागर करें जिस तक कि वे सेवाओं के कुशल तथा साम्य रूप से मुहैय्या कराने के भार को वहन कर सकें। इसलिए इस विश्लेषण में (i) उन संस्थाओं तथा संगठनों की पहचान करना जिनके कि अवसंरचनात्मक प्रावधान के लिए प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से जिम्मेदारियां प्रदान की गयी हैं (ii) संविभाजन या परस्पर व्यापन वाले क्षेत्रों की पहचान करना (iii) इस प्रभाव का मूल्यांकन कि उसने अवसंरचना मुहैय्या करने तथा उसका प्रबन्ध कराने पर क्या प्रभाव होगा; तथा (iv) सेवा मुहैया करने में निजी क्षेत्रों की भूमिका की समीक्षा करना और अवसंरचनात्मक सेवाओं के विकास तथा प्रबंधन में सार्वजनिक–निजी साझेदारी की संभाव्यता कितनी है को शामिल करती है।

इस विश्लेषण को इस प्रकार निरूपित किया जाता है कि उसमें निम्न प्रश्नों पर प्रकाश डाला जाए। जैसे कि त्रिस्तरीय सरकार के बीच प्राधिकारों की डी–ज्यूरी तथा डी–फेक्टों का विभाजन किस तरह का है और ये संवैधानिक तथा विधिक उपेक्षाओं से किस प्रकार सम्पृक्त हैं? शहरी प्रशासन तथा सार्वजनिक सेवाएं मुहैया कराने पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है? क्या सार्वजनिक सेवा अभिकरणों के उत्तरदायित्वों तथा गतिविधियों पर कोई परस्पर व्याप्ति है? क्या इनके उद्देश्य तथा गतिविधियां एक दूसरे के पूरक अथवा विभेदक है? इनके अन्तर अभिकरण समन्वय के लिए मौजूदा तंत्र क्या हैं?

सारणी: 18 संस्थागत दायित्व			
शहर अवसंरचना	**योजना और विकल्प**	**निर्माण**	**ऑपरेशन और रखरखाव**
जल आपूर्ति			
सीवर			
निकास			
बरसाती जल के निकास			
ठोस कचरा निपटाना			
नगर निगम सड़कें (फ्लाई ओवरों सहित)			
स्ट्रीट लाइटें			

सारणी: 19 शहर अवसंरचना प्रावधान में निजी क्षेत्र की भूमिका	
शहर अवसंरचना	**निजी सैक्टर (क्षेत्र) की भूमिका**
जल आपूर्ति	
सीवर	
निकास	
बरसाती जल के निकास	
ठोस कचरा निपटाना	
नगर निगम सड़कें (फ्लाई ओवरों सहित)	
स्ट्रीट लाइटें	

IV. शहर के लिए विजन तैयार करना

एक सीडीपी को तैयार करने के लिए किसी शहर के लिए विजन तैयार करना एक प्रमुख कार्य है। विजन एक तरह का विवरण है जिसमें दिए गए समय के भीतर शहर को कहां ले जाना चाहते हैं उसकी जानकारी दी जाती है और प्राय: इसमें स्पष्ट आशाओं के अर्थों में व्यक्त किया जाता है। ये शहर की संभाव्यता को परिभाषित करता है और तुलनात्मकता तथा तुलनात्मक लाभों, मूल्यों तथा शहर के निवासियों की प्राथमिकताओं, राज्य के साथ शहर के संबंधों, राष्ट्रीय तथा ग्लोबल आर्थिकी के अर्थों में इसके अद्वितीय विशेषताओं को प्रतिबिम्बित करता है और हाँ, यह शहर की ऐतिहासिक तथा भौतिक विशिष्टताओं को भी प्रतिबिम्बित करता है। विज़न शहर के विकास के लिए संसक्तिपूर्वक कार्य करने के बारे में एक स्टाकहोल्डर की शक्तियों को पंक्तिबद्ध करता है। शहरों को चाहिए कि वे भविष्य के बारे में एक सिलसिलेवार विचार करें और भविष्य के स्वरूप के अनुसार ही नीतियों को निरुपित करें। सभी उद्धेश्य, नीतियां, कार्यक्रम तथा परियोजनाएं शहर के विजन से सीधे सीधे जुड़ी होनी चाहिएं।

विभिन्न आर्थिक अवसंरचना क्षेत्र से तथा शहर के विभिन्न इच्छुक समूहों से उठ रही प्रतिस्पर्धी मांगों को संतुलित करने के लिए एक कॉमन विजन का विकास करने हेतु जनमत आधार तैयार करने के महत्वपूर्ण प्रयास करने अपेक्षित हैं। कॉमन विजन की एक सोच को प्राप्त करने के लिए ''मील के पत्थर'' को चुनना उपयोगी है और उन लक्ष्यों जैसे कि सभी को सेवाओं का न्यूनतम स्तर प्रदान करने के प्रावधान; बजट प्रस्तावों के निरुपणों में सार्वजनिक खुलासे तथा पारदर्शिता; सेवा मुहैय्या कराने तथा प्रबंधन और इस से जुड़े दूसरे कार्यों के मामलों में एक प्रणाली की शुरूआत करना; आदि को शामिल करना चाहिए। विजन का विकास करने में शहरों को उन मानदण्डों के युग्म का अवश्य चयन करना चाहिए जो जनरम घटकों से सीधे जुड़े होते हैं। अत: यह आवश्यक है कि जब शहर के विजन में परिणामों तथा मील के पत्थर को परिभाषित करें तो वे ये सुनिश्चित करें कि ये मापने योग्य हैं और उनकी एक समय सीमा है।

सारणी 20: विजन और लक्ष्य

विजन और लक्ष्य	वर्ष		
	2010	2015	2020
क्षेत्रीय ऐजण्डा			
जल आपूर्ति			
सीवर			
स्वच्छता			
ठोस कचरा प्रबंधन			
निकास/बरसाती जल नाले			
शहरी परिवहन			
परम्पराएं			
सुधार एजेण्डा			
विकेन्द्रीयकरण			
भूमि तथा आवासीय बाज़ार			
पारदर्शिता व जवाबदेही			
सामुदायिक प्रतिभागिता			
वित्तीय प्रबंधन सिस्टम			
नगर निगम वित्तीय प्रावधान			
शहरी गरीबों के लिए बजट तैयार करना			

जनरम के परिणाम

- *सेवाओं के न्यूनतम स्तर के लिए सर्वव्यापक पहुंच*
- *प्लानिंग तथा अभिशासन के लिए पूरे शहर के फ्रेमवर्क को स्थापित करना*
- *नगर निगम स्तरों पर आधुनिक व पारदर्शी बजटिंग लेखाकरण, वित्तीय प्रबंधन आदि*
- *नगर निगमों तथा दूसरे सेवा मुहैय्या कराने वाले संस्थानों के लिए वित्तीय संपोषितता*
- *नगर निगम सरकारों के मूल कार्यों में ई–गवर्नेंस की शुरुआत करना*
- *शहरी सेवा मुहैयाकरण तथा प्रावधान में पारदर्शिता व जवाबदेही*

V. नीतियों पर कार्य करना

शहर कहां पर है और इसे कहां तक ले जाना है इसके बीच की दूरी को विभिन्न नीतियों तथा कार्यक्रमों का अनुसरण करके कम कर अर्थात पाटा जा सकता है। यह आवश्यक है कि इस दूरी को कम करने के लिए वैकल्पिक नीतियां तय की जाती हैं और उनका ध्यानपूर्वक मूल्यांकन किया जाए। जनरम के परिप्रेक्ष्य में, किसी एक नीति अथवा नीतियों के समूह का चयन उसके लक्ष्यों, उद्देश्यों तथा सुधार एजेण्डा के प्रति उनके योगदान द्वारा मार्ग निर्देशित होना चाहिए।

किसी भी सी॰डी॰पी॰ की रूपरेखा तैयार करने में नीतियों का चयन करना नितांत महत्वपूर्ण है और ये जरूरी है कि इसे मुख्य-मुख्य स्टाकहोल्डरों के विचारों के व्यापक आदान-प्रदान से किया जाए। एक ऐसी नीति जो सेवा प्रावधानों के साथ शहरी गरीबों से जुड़ी हो उसकी तुलना वरीयता उस नीति से अधिमान्यता की जाए जो इसके संभावित लाभप्राप्तकर्ताओं या लक्ष्य समूहों के किसी संदर्भ के बिना सेवाओं को बढ़ाने का उद्देश्य रखती हैं। कोई भी एक ऐसी शहरी नवीकरण नीति, जो परिवर्तन चरण में गरीबों के हितों से जुड़ी हो, को दूसरी नीतियों की बनिस्पत उच्च प्राथमिक दी जाए और जो विभिन्न प्रभावित समूहों के बीच कोई भेद न करती हो। उद्देश्य उसके प्रभाव को अधिकतम करने पर है चाहे ये जलापूर्ति परियोजना हो या फिर कोई सुधार एजेण्डा जैसे कि शहरी भूमि (सीमा तथा नियमन) अधिनियम, 1976 के निरसन का घटक ही क्यों न हो।

नीति निरूपण के कार्यों में निम्न बातें पूछना उपयोगी है: क्या यह नीति विजन को प्राप्त करने में मदद करेगी या ये नीति शहर को विजन के करीब लाने में मददगार साबित होगी? क्या यह नीति जनरम के निष्कर्षों को हासिल करने में मदद करेगी? किसी नीति के चयन में पसंद बताना जरूर शामिल किया जाता है; किन्हीं दो नीतियों का उनके प्रभाव में समान महत्व नहीं होता है। चयन में इस बात की जरूरत होती है कि वे प्रस्तुत हो रहे परिणामों की संभाव्यता से निर्देशित हो और इनका मूल्यांकन ''निवेश'' के बजाय ''परिणामों'' के अर्थों में होना चाहिए। चयन प्राय: संस्थानिक क्षमताओं को निर्धारित करके तथा कार्यान्वयन के वित्तीय साधनों से निर्धारित किया जाता है, हालांकि नीतियां इस तरीके से चयन की जाएं जिस तरीके से वे विजन को प्राप्त करने के लिए संस्थानिक तथा वित्तीय क्षमताओं को आगे बढ़ा सकें।

सारणी: 21 नीति के मानदण्ड

मानदण्ड	वैकल्पिक नीतियां और कार्यक्रम

नीति प्लान इस तरह का हो कि वह किसी शहर के विजन अथवा संदर्श को हासिल करने के लिए हो ताकि भविष्य में इसके भीतर कोई उतार चढ़ाव न आए।

VII. शहर निवेश योजना और वित्तीय नीतियां

शहर निवेश योजना (सी॰आई॰पी॰) निवेश के उस स्तर का एक प्राक्कलन उपलब्ध कराता है जो कि सी॰डी॰पी॰ को क्रियान्वित करने के लिए जरूरी होगा। यह एक प्राक्कलन तथा मोटा-मोटा अनुमान है और जो सेवा प्रावधानों तथा अपग्रेडेशन के लिए वित्तीय मानकों या प्रतिमानों को उपयोग करके प्राप्त आधारों पर निवेश का एक क्रम निर्धारित करता है और सुधार एजेण्डा को क्रियान्वित करने की लागत का सीधे-सीधे प्राक्कलन करता है। एक निवेश योजना निम्न प्रश्नों का उत्तर प्राप्त करके ही निरूपित की जाए: जैसे कि शहर की जनसंख्या के लिए 150 लीटर जल मुहैया कराने के लिए कितने निवेश की जरूरत पड़ेगी? यदि वह क्षेत्र शहर में फैली सड़कों से नीचे है और उसे उसके मौजूदा स्तर से शहर के कुल क्षेत्र की ऊंचाई से लगभग 20 प्रतिशत ऊंचा उठाया जाना हो तो निवेश का क्रम क्या होना चाहिए? यदि खुले नाले वाले सिस्टम को जमीन के भीतर वाली सीवेज सुविधा में ढांपना होगा तो उसके लिए शहर को कितने निवेश की जरूरत पड़ेगी?

जैसी कि सी॰डी॰पी॰ में दिया गया है विजन को वित्त देने के लिए विकल्पों तथा नीतियों पर विचार करना, एक सम्पृक्त, लेकिन यह एक महत्वपूर्ण पहलु भी है। क्या इसे संसाधनों का जुटाव करके स्थानीय सरकारों द्वारा वित्त प्रदान किया जाएगा या सरकार दूसरी श्रेणियों तथा वित्तीय संस्थाओं के साथ साझेदारी करके वित्त प्रदान किया जाए? क्या शहर पूंजी बाजार की शरण लेगा? पूंजी बाजार मे पहुंचने के लिए शहर को क्या करने की जरुरत पड़ेगी? इस विजन को पूरा करने के लिए क्या निजी क्षेत्रों को बढ़ावा दिया जाएगा? निजी क्षेत्रों से निवेश जुटाने के लिए क्या-क्या कदम उठाए जाने अपेक्षित होंगे? किस सीमा तक एक शहर इसके सिलसिलेवार जांच कर पाएगा कि कहीं वित्तीय विकल्प सी.डी.पी. का मूल्य बढ़ा तो नही देंगे।

सारणी 22 वित्तीय विकल्पों का प्रोफार्मा

वित्तीय विकल्प	अतिरिक्त संसाधनों का आंकलन
नगर निगम सरकारों के खुद के संसाधन	
राज्य सरकार अनुदान और ऋण	
वित्ती संस्थान	
पूंजी बाजार	
विदेशी वित्त	
केन्दीय सरकार के अनुदान	
निजी क्षेत्र	

सारांश

निम्नलिखित बिन्दुओं पर प्रकाश डालते हुए सी॰डी॰पी॰ के मुख्य-मुख्य लक्षणों/विशेषताओं के सारांश प्रस्तुत करना उपयोगी है:—

- शहर के प्रोफाइल का विश्लेषण क्या प्रदर्शित करता है? अवसर कहां पर है और कौन-कौन सी मुख्य रुकावटें हैं?
- उपलब्ध अवसरों तथा रुकावटों के चलते शहर एक मध्यावधि संदर्श में शहर को कहां ले जाना चाहते हैं हालांकि विजन भविष्य पर विचार करता है। विजन में वास्तविकता को भी देखा जाए कि निर्धारित समय में क्या उपलब्धियां रही हैं।
- इस विजन को प्राप्त करने के लिए कौन से नीतिक विकल्प उपलब्ध हैं? वैकल्पिक नीतिक विकल्पों की लागतें तथा लाभ क्या-क्या हैं? कम से कम लागत पर अथवा न्यूनतम प्रभाव पर इस विजन को प्राप्त करने में कौन सी नीतियां शहर की मदद करेंगी?
- इस विजन को क्रियान्वित करने के लिए औसत कितने निवेश की जरुरत होगी। इस सी॰डी॰पी॰ को क्रियान्वित करने के लिए संसाधनों के जुटाव हेतु कौन-कौन से विकल्प हैं?
- इस सी॰डी॰पी॰ के कुशलतापूर्वक क्रियान्वयन के लिए इस जनरम में दिए गए सुधारों के अलावा और कौन से सुधार हो सकते हैं?

यह टूल किट एक (सी॰डी॰पी॰) को तैयार करने के लिए उपाय निर्धारित करती है। इस बात को अवश्य समझा जाए कि सी॰डी॰पी॰ को तैयार करना कोई हँसी मजाक नहीं है। इस टूल किट में दिए गए तरीकों का इसमें अवश्य अनुसरण किया जाए। इसमें इतनी ढील अवश्य दी जाए कि जो शहर के पर्यावरण तथा संस्थागत अभिन्यास के अनुरूप हो उसे अवश्य जोड़ लिया जाए। इसके अलावा, इस टूल किट में जहां संभव हुआ है अच्छे-अच्छे उदाहरण, तथा संदर्भ दस्तावेज और दूसरे तालिकाओं में प्रारूप भी दिए गए हैं।

परिशिष्ट

जनरम के अन्तर्गत अनुमत गतिविधियां

(I) शहरी नवीकरण अर्थात् शहर क्षेत्रों के भीतरी (पुराने) भागों के पुन: विकास करना (इसमें तंग गलियों को बन्द करना, भीड़-भाड़ को कम करने के लिए औद्योगिक/कामर्शियल स्थापनाओं को ''गैर-कंफर्मिंग'' क्षेत्रों से (शहर के भीतरी भाग) कंफर्मिंग क्षेत्रों (शहरी आबादी से दूर) में शिफ्ट करना, नए/उच्च क्षमता वाले पाइपों से पुराने व जीर्णशीर्ण हो गए पानी के पाइपों को बदलना, सीवेज नालों का नवीकरण /ठोस कचरे का निपटान सिस्टम आदि जैसी मदों को शामिल करना होगा)। इस कार्यक्रम के इस घटक में भूमि अधिग्रहण की लागत को वित्त पोषित नहीं किया जाएगा।

(II) पानी को खारी होने से बचाने हेतु, जहां कहीं आवश्यक हो, पौधे लगाने सहित जलापूर्ति।

(III) सीवेज तथा ठोस कचरा प्रबंधन।

(IV) नालों/बरसाती जल के नालों का निर्माण करना व उनका परिशोधन।

(V) शहरी परिवहन।

(VI) परिवहन के जाम को हटाने के लिए मुख्य मार्गों/उप मुख्य मार्गों तथा पुलों को बिछाना/सुधार करना/ उन्हें चौड़ा करना।

(VII) मेट्रो तथा मेगा सिटी के चारों ओर मुद्रिका मार्ग तथा बाई पासों का निर्माण करना बशर्ते कि कुछेक लागत वसूली उपाय जैसे कि टोल किराए आदि लगाए जाएं।

(VIII) बस तथा मेगा सिटी के चारों ओर मुद्रिका मार्ग तथा बाई पासों का निर्माण करना।

(IX) पर्यावरण सुधार तथा शहर सौंदर्यीकरण योजनाएं।

(X) कामकाजी महिला होस्टल, मैरिज हालों, वृद्धा तथा दीनहीन बच्चों के लिए गृहों, सामुदायिक शौचालयों सहित रैन बसेरों का निर्माण।